दैनिक जागरण
शनिवार, 9 जनवरी, 2016 : पौष कृष्ण 14, वि. 2072

संयम की चाबी से सफलता के प्रत्येक द्वार खोले जा सकते हैं

चिंतित करते संकेत

यह आशंका गहराना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है कि पठानकोट में वायु सेना के ठिकाने पर हमला करने आए आतंकियों को किसी न किसी स्तर पर अंदर से भी मदद मिली। अभी तक केवल पुलिस अधीक्षक सलविंदर सिंह और उनके साथी ही संदेह के घेरे में थे, लेकिन अब एयरबेस की निगरानी में सहायक कर्मी भी शक के दायरे में आ गए हैं। इनमें एक लाइनमैन खास तौर पर है। इसके अतिरिक्त यह पहले दिन से ही स्पष्ट हो रहा है कि किसी न किसी स्तर पर अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर भी चूक हुई। हालांकि सीमा सुरक्षा बल ने सीमा की सुरक्षा में चूक से इंकार किया है, लेकिन अगर कहीं कोई गफलत नहीं हुई तो क्या आतंकी आसमान से आ टपके? अगर इस अंदेशे की पुष्टि होती है कि भारतीय सीमा में घुसपैठ से लेकर एयरबेस में दाखिल होने तक आतंकियों की मदद हमारे अपने लोगों ने की तो पूरे सुरक्षा तंत्र की नए सिरे से समीक्षा भी करनी होगी, बल्कि गफलत के लिए जिम्मेदार लोगों को कठघरे में भी खड़ा करना होगा। इसके साथ ही हर स्तर पर यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि सीमा पार सुरक्षा में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए। सच तो यह है कि यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। यह पहली बार नहीं जब सीमा पार से आतंकियों ने घुसपैठ कर जम्मू-कश्मीर अथवा पंजाब में किसी महत्वपूर्ण ठिकाने पर हमला किया हो। पिछले तीन-चार सालों में कम से कम ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जब आतंकी सीमा से दाखिल होकर बड़ी वारदात को अंजाम देने में सफल रहे। पठानकोट के पहले गुरदासपुर में आतंकी इसी तरह हमला करने में सक्षम रहे थे। इसके पहले जम्मू और कश्मीर घाटी में।

आतंकियों की घुसपैठ के ये मामले यही बताते हैं कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा में आतंकियों की घुसपैठ के लिए जैसी चौकसी होनी चाहिए थी वह नहीं है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट हो रहा है कि पुरानी भूलों से जरूरी सबक सीखने से इंकार किया गया। यह सही है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर कई इलाके दुर्गम हैं, लेकिन अब जब हर तरह की तकनीक के साथ-साथ संसाधन भी उपलब्ध हैं तो फिर सीमा की सुरक्षा को अभेद्य बनाने का लक्ष्य पूरा न होना कई सवाल खड़े करता है। यह अजीब बात है कि पंजाब में पाकिस्तान से लगने वाले कई इलाकों में पक्की सड़कें तक नहीं हैं। चूंकि सीमा पार से हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी भी जारी है इसलिए अभेद्य सुरक्षा के दावों की पोल ही खुलती है। यदि सुरक्षा में कहीं कोई खामी नहीं तो फिर क्या कारण है कि पंजाब में सीमा पार से नशीले पदार्थों की तस्करी रुक नहीं पा रही है? सीमा की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता में होनी ही नहीं चाहिए, बल्कि दिखनी भी चाहिए। यह न केवल जम्मू-कश्मीर और पंजाब में होना चाहिए, बल्कि बांग्लादेश से लगती सीमा पर भी। यदि बार-बार की गफलत और उसके दुष्परिणाम स्वरूप होने वाले नुकसान के बावजूद सबक नहीं सीखा जाता तो आतंकी हमलों का खतरा और बढ़ेगा ही।

पद के साथ जिम्मेदारी

उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के तहत अप्रत्यक्ष वोट से जनता ने अपने नए जिला पंचायत अध्यक्ष के चुन लिए हैं। करीब एक हफ्ते बाद 14 जनवरी से इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही नगरीय इलाकों को छोड़ बाकी हिस्से के विकास की सीधी जिम्मेदारी इन्हीं कंधों पर आ जाएगी। लोकतंत्र की विशेषता है कि उसके नुमाइंदे अच्छा-बुरा जैसा भी काम करें, आखिर में अगले चुनाव में जनता हिसाब बराबर अवश्य करती है। न्यायालय के अलावा जन प्रतिनिधियों के ऊपर जनता का ही अंकुश रहता है, या यूं कहा जाए कि परोक्ष डर रहता है। अन्यथा उनके पास पांच साल तक संविधान प्रदत्त ऐसी शक्तियां मौजूद रहती हैं जिनका इस्तेमाल वह मनमर्जी से करना चाहेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष का पद अत्यंत प्रभावशाली और प्रतिष्ठापूर्ण माना जाता है, शायद इसीलिए सदस्य के रूप में जनता का वोट हासिल करने के बाद भी उन्हें तरह-तरह के हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। सत्ता में आरूढ़ पार्टी भी इसे अपनी नाक का सवाल बना लेती है, और परिणाम भी उसी के पक्ष में जाता रहा है। पिछले चुनावों में तत्कालीन सत्ता पक्ष बसपा को पचास से ज्यादा जिलों में अपने अध्यक्ष मिले थे। इस बार समाजवादी पार्टी ने 59 जिलों में विजय हासिल की है, इनमें से तीन दर्जन तो निर्विरोध जीते हैं।

जिला पंचायत अध्यक्ष के संवैधानिक पद तक पहुंचने के लिए अपने राजनीतिक कौशल का प्रदर्शन करने वाली 74 राजनीतिक हस्तियों को अब अपनी जनोन्मुखी प्रतिभा दिखाने का समय आ रहा है। सबसे पहले तो यह याद रखना होगा कि सरकार की योजनाओं का ही शत-प्रतिशत क्रियान्वयन हो जाए तो जनता सिर-माथे पर बिठाने से पीछे नहीं रहती। तमाम विशेषताओं वाले इस प्रदेश के जिलों में कई तरह की समस्याएं हैं, कुछ पूरे राज्य में एक जैसी तो कुछ क्षेत्र विशेष के लिहाज से अलग-अलग। जल संक्षरण, नदी संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, वन संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण जैसी समस्याएं तो सर्वव्यापी हैं। जबकि सिंचाई, पेयजल, सड़क, शिक्षा, विद्युतीकरण, पुल-पुलिया निर्माण आदि की समस्या तो हर जिले की अपनी हैं। हाल के वर्षों में तेज शहरीकरण ने अनियोजित विकास की समस्या को सुरसा के मुंह की तरह फैलाया है। जिला पंचायत अध्यक्षों को तय करना है कि किस समस्या के समाधान को वह प्राथमिकता देते हैं, अपने जिले में कौन सा विकास का मॉडल पेश करते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि वह अपने पूर्ववर्तियों से आगे निकल कर रचनात्मक विकास की दिशा में आगे बढ़ने में कामयाब होंगे।

भारत से दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने की अपेक्षा कर रहे हैं ब्रह्मा चेलानी

पलटवार का इंतजार

पठानकोट एयर बेस में आतंकियों का चार दिनों का घेरा 26 नवंबर, 2008 को हुए मुंबई आतंकी हमले के समान था। दोनों ही वारदातों में पाकिस्तानी आतंकी पेशेवर ढंग से प्रशिक्षित थे, उनके पास भारी मात्रा में हथियार थे और उन्हें खास आत्मघाती मिशन के लिए उनके आकाओं ने भेजा था। मुख्य अंतर यह है कि मुंबई में आतंकियों ने नागरिक स्थलों पर हमले किए, जबकि यहां उन्हें दिया गया लक्ष्य एक विस्तृत सैन्य सुविधा वाला इलाका था। अत्यंत महत्वपूर्ण भारतीय एयर बेस को लंबे समय तक घेरे रखना मुंबई में सॉफ्ट टारगेट पर हमले की तुलना में आतंक फैलाने वालों के लिए बड़े लक्ष्य का संकेत देता है। यह भी महज संयोग नहीं था कि पठानकोट हमला और अफगानिस्तान के मजार-ए-शरीफ में भारतीय वाणिज्य दूतावास की घेरेबंदी का समय एक ही था। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इसे आउटसोर्स किया था और दोहरे हमले भारत को नए साल के उपहार के तौर पर दिए गए थे। अगर आतंकियों ने कुछ लोगों को बंधक बनाने में सफलता हासिल कर ली होती तो भारत अपने आप घेरेबंदी में आ सकता था।

आतंकवाद की मुसीबत से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए किसी देश का नेतृत्व सबसे असली चीज होती है। भारत 1989 से ही नेतृत्व का संकट झेलता रहा है। इस दौरान पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर में विद्रोह भड़काने से लेकर अब पूरे भारत में आतंकी हमले का जाल बुनने लगा है। उसकी ही कारस्तानी की वजह से कश्मीर घाटी के तीन लाख कश्मीरी पंडितों को वहां से रातोंरात भागना पड़ा था। नरेंद्र मोदी की चुनावी जीत इस राजनीतिक कमजोरी को समाप्त करने के लिए एक शक्तिशाली नेता की भारतीयों की चाहत की अभिव्यक्ति थी। मोदी की जीत के बावजूद सीमा पार आतंकियों ने भारत के संकल्प की बारंबार परीक्षा ली है- हेरात से गुरदासपुर और उधमपुर होते हुए पठानकोट तक। हर बार भारत परीक्षा में विफल हुआ है। वाजपेयी युग से ही ऐसा चल रहा है। पठानकोट हमला एक युद्ध की तरह ही है। मोदी के सामने यह पहली गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती थी। लेकिन मोदी का नेतृत्व सामने आकर लड़ने से लेकर भारतीय जनता को विश्वास दिलाने तक, लगभग हर मामले में सकपकाया लगा। पूरे घटनाक्रम के दौरान उन्होंने जो एकमात्र बयान दिया भी वह एक तरह की खानापूरी ही लगा। जिस तरह उन्होंने पेरिस हमले को 'मानवता पर हमला' कहा था ठीक उसी तरह पठानकोट हमले को 'मानवता के शत्रुओं' द्वारा की गई कार्रवाई बताया गया। वह इसे 'भारत के शत्रुओं' द्वारा किया गया हमला कहने के लिए भी अपने को तैयार नहीं कर पाए।

कार्रवाई के लिहाज से पठानकोट का मामला इसका सटीक उदाहरण है कि इस प्रकार के अभियानों को किस तरह वैसे रूप में संचालित नहीं किया जाना चाहिए जैसा पठानकोट में किया गया। हमले की पहले ही खुफिया जानकारी दिल्ली को मिल जाने के बावजूद आतंकी न सिर्फ बेस में घुस गए, बल्कि उन्हें बाहर निकालने का अभियान संयुक्त कमान के बिना बहुत ही खराब ढंग से सोचा गया और अमल में लाया गया। युद्ध में अच्छे जनसंपर्क की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी सरकार के पास तो शांति के वक्त भी जनता से संवाद की सही रणनीति नहीं है। पठानकोट हमले के दौरान अधिकारियों ने भ्रमित और परस्पर विरोधी बयान दिए। कुछ भी कहें, इस संकट ने सरकार के सामरिक भोलेपन को ही उजागर किया। बेस के अंदर जब गोलाबारी चल ही रही थी, सरकार ने पाकिस्तान में अपने आकाओं से आतंकियों की बातचीत और अन्य प्रमाण इस्लामाबाद को मुहैया करा दिए। इस खुशफहमी में ऐसा किया गया कि आतंक फैलाने वाले आतंक को अंजाम देने वालों के पीछे लग जाएंगे। वह भी तब जब भारत को मुंबई मामले में कड़वा अनुभव मिल चुका है। लगभग रियल टाइम में सुबूत सौंपकर भारत इस्लामाबाद से क्या हासिल करने की उम्मीद कर रहा था?

घेरेबंदी के चौथे दिन नई दिल्ली का यह रहस्योद्घाटन इससे भी अधिक हास्यास्पद था कि नवाज शरीफ की तरफ से आए फोन पर मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से भारत द्वारा उपलब्ध कराई गई 'विस्तृत और कार्रवाई लायक सूचना' पर 'कठोर और तत्काल कार्रवाई करने' को कहा है और शरीफ ने 'आतंकियों के खिलाफ शीघ्र और निर्णायक कार्रवाई करने' का आश्वासन दिया है। अगर शरीफ के पास अधिकार हो भी तो क्या वह उन तत्वों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं जो भारत को हजार घाव देना चाहते हैं? स्पष्ट तौर पर पाकिस्तान के जनरल भारत के साथ अमन का विरोध करते हैं। निर्णायक शक्ति उनके पास है और सेना तथा आइएसआइ नागरिक शक्ति को लांघने में सक्षम हैं। भारत पाकिस्तान के साथ जिन प्रमुख मुद्दों-आतंकवाद, घुसपैठ, सीमा पर शांति, परमाणु सुरक्षा आदि पर बातचीत करना चाहता है वे ऐसे हैं जिन पर अंतिम मुहर सेना की लगनी है। इसलिए मोदी ऐसी शक्तिहीन पाकिस्तान सरकार से शांति कायम करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं जिसने विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों का अधिकार सेना के हाथों सौंप दिया है? पाकिस्तानी सेना ने अपने यहां की निर्वाचित सरकार को शक्तिहीन बना दिया है, जबकि भारत सरकार आतंकवाद को हराने में सक्षम सेना को शक्तिहीन बना रही है। यह पठानकोट घेरेबंदी के समय भी साफ था जब सेना के तैयार कमांडो को कार्रवाई के लिए तत्काल कहने की जगह सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कमांडो को विमान से वहां ले जाने का फैसला किया।

खुले युद्ध से कम में बहुत कुछ है जो भारत आतंक को प्रश्रय देने वालों के खिलाफ कर सकता है। लेकिन इसे कार्रवाई में बदलने के लिए राजनीतिक इच्छा और सफलता के लिए स्पष्ट रणनीतिक लक्ष्य होने चाहिए। आज दुर्भाग्य से दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टि या पाकिस्तान नीति ही नहीं है। मोदी जब से सत्ता में आए हैं, भारत ने पाकिस्तान के मुद्दे पर कम से कम छह बार यू टर्न लिया है। लगभग हर मौसम में नई दिल्ली नई पाकिस्तान नीति सामने ले आई। गैरपारंपरिक युद्ध को गैरपारंपरिक तरीके से ही लड़ा जाना चाहिए। गैरपारंपरिक युद्ध में परमाणु हथियारों की कोई डराने वाली अहमियत नहीं है। दुनिया के सबसे दुर्जेय परमाणु हथियार भंडार के बावजूद सोवियत संघ बिखर गया। भारत को क्यों किसी को बार-बार आक्रमण करने का मौका देना चाहिए, जबकि यह पाकिस्तान से आबादी में सात गुना, जीडीपी के मामले में उससे 12 गुना बड़ा है और सैन्य शक्ति में भी उससे शक्तिशाली है? कोई भी देश सिर्फ शांति चाहकर शांति नहीं हासिल कर सकता है। शांति हासिल करने के लिए अगर शांति भंग की जाती है तो दूसरे पक्ष को यह बताने के लिए मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए कि शांतिपूर्ण सहयोग के लाभ दुश्मनी से अधिक हैं।

(लेखक जाने-माने सुरक्षा विश्लेषक और सेंटर फार पालिसी रिसर्च में प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

सेना और सरकार

◆ पाकिस्तानी सेना ने अपने यहां की निर्वाचित सरकार को शक्तिहीन बना दिया है, जबकि भारत सरकार आतंकवाद को हराने में सक्षम सेना को शक्तिहीन बना रही है

अल्पमत की मनमानी

राज्यसभा के सहारे सरकार से शासन का अधिकार छीन रहे विपक्षी दलों के कारण लोकतंत्र पर खतरा उत्पन्न होते देख रहे हैं ए. सूर्यप्रकाश

संसद में कामकाज न होने के परंपरागत विलाप के साथ संसद के शीत सत्र का समापन हो गया। शीतकालीन सत्र में हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार बजट सत्र को समय से पूर्व बुलाने पर विचार कर रही है। उसका इरादा महत्वपूर्ण विधेयकों पर विपक्ष को सहमत करने का है, लेकिन इसके आसार कम ही हैं कि उसकी यह कोशिश सफल हो सकेगी। पिछले दो सत्रों में दोनों सदनों में तरह-तरह के बहाने वाले राजनीतिक मुद्दों पर कई बार व्यवधान हुए, जिसकी वजह से मोदी सरकार उन मसलों पर विधायी कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकी जिसका उसने प्रस्ताव किया था। सरकार की लाचारी ने इस सवाल को फिर उठाया है कि संसद को बाधित करने के दुराग्रह पर उतारू विपक्ष क्या एक निर्वाचित सरकार की विधायी योजनाओं में बाधा पहुंचाकर 2014 के जनादेश को एक तरह से पलट सकता है? हालांकि देश के उच्चतम सदन के कामकाज में विफलता के उत्तरदायित्व को लेकर सरकार और विपक्षी दल एक-दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन इस बार क्या गड़बड़ी हुई, इसे लेकर संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू का तर्क सच्चाई के ज्यादा निकट लगता है। उन्होंने कांग्रेस पर दोनों सदनों में कार्यवाही बाधित करने के लिए रोजाना नए-नए बहाने 'गढ़ने' का आरोप लगाया। कांग्रेस की व्यवधान पैदा करने वाली इस तकनीक के कारण राज्यसभा का लगभग आधा समय व्यवधान और स्थगन में चला गया।

भारतीय जनता पार्टी उच्च सदन में अल्पमत में है और सदन में लगभग 70 सदस्यों वाली कांग्रेस अपनी इस संख्या का उपयोग सत्तारूढ़ भाजपा के विधायी एजेंडे को रोकने के लिए कर रही है। अधिक चिंताजनक उच्च सदन में प्रश्न काल का वस्तुतः समाप्त हो जाना है। संसद के कामकाज पर नजर रखने में अच्छा काम कर रही पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च ने कहा है कि इस बार राज्यसभा में पूरे सत्र में प्रश्न काल सिर्फ 2.4 घंटे चला, जिसका मतलब है कि इसने अपने लिए आवंटित समय में सिर्फ 14 प्रतिशत काम किया। प्रश्न काल के न चलने से अधिक संसदीय प्रक्रिया की विफलता का और कोई प्रतीक नहीं हो सकता है। सरकार की जवाबदेही के लिहाज से प्रश्नकाल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और निगरानी के अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिहाज से संसद के लिए भी वह अहम है। पिछले साठ साल में यह उन सांसदों के लिए सबसे प्रभावी समय रहा है जो सरकार को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। यह सवाल उठाने और एक तरह से मंत्रियों से पूछताछ करने का इस तरह का अवसर देता है कि मंत्री मुद्दे समझने और अपने उत्तर तैयार करने में घंटों समय लगाते हैं। यही कारण है कि प्रश्नकाल मंत्रियों के लिए सबसे कठिन समय होता है। इसलिए जब विपक्ष मुद्दे उठाता है और प्रश्नकाल बाधित करता है तो सदन के सबसे खुश सदस्यों में केंद्रीय मंत्री होते हैं। व्यवधान पैदा करने वाले सांसद जवाबदेही के विचार को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इसके चलते दूसरे सदस्य, खासकर विपक्ष में बैठने वाले सांसद सरकार के सामने सवाल रखने और जवाब मांगने का अधिकार गंवा देते हैं। यह देखना सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष ने इतने महत्वपूर्ण संसदीय हथियार को बर्बाद कर दिया, जो सरकार को रास्ते पर लाने के लिए था।

दूसरा उल्लेखनीय तथ्य संसद का बढ़ता खर्च है। पिछले छह दशकों में संसद के कामकाज पर खर्च असाधारण रूप से बढ़ा है। हाल के वर्षों में यह करीब दो करोड़ रुपये प्रतिदिन या 29 हजार रुपये प्रति घंटा हो गया। ये आंकड़े खर्च में भारी बढ़ोतरी को दिखाते हैं और इसलिए स्वाभाविक है कि लोग चाहते हैं कि संसद में कामकाज हो। अगर लोग धन का उपयोग होता न पाएंगे तो संसदीय व्यवस्था की प्रभावोत्पादकता पर सवाल उठने लगेंगे। अगर एक निर्वाचित सरकार को अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए विधायी कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तो पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया व्यर्थ हो जाएगी। लोकतंत्र अनेकता और मतभिन्नता के लिए है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की सामाजिक विविधता राजनीतिक विविधता में बदल गई है और यह धर्म से लेकर क्षेत्र और जाति तक हितों के विस्तृत आयाम का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक दलों के बहुतायत में उदय का कारण बनी है। जो हाल बन रहा है उससे लोग अपनी राजनीति में विविधता को शासन व्यवस्था में रुकावट के तौर पर देखने लगेंगे। यह स्थिति एकदलीय शासन के तर्क या अराजकता के रास्ते को बढ़ावा देगी। इसके अपने खतरे हैं। जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी के वक्त तक भारत में एक तरह से एकदलीय शासन था। कांग्रेस पार्टी न सिर्फ केंद्र में सरकार में थी, बल्कि अधिकांश राज्यों में उसकी ही सरकार थी। ऐसे समय में बहुमत की निरंकुशता से कभी-कभी चिंता होती थी। इस निरंकुशता ने दुर्भाग्यवश कुछ सबसे अधिक निर्दयी संविधान संशोधन किए, जिनमें से एक के तहत संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं में कार्यवाही चलाने और कानून बनाने के लिए कोरम की जरूरत ही समाप्त कर दी गई।

1989 में राजीव गांधी सरकार की हार के बाद से किसी सरकार के पास राज्यसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं रहा। तब से केंद्र में गठबंधन सरकारें ही सत्ता में आईं, जिनमें से कुछ चुनाव पूर्व गठबंधन वाली सरकारें थीं और कुछ चुनाव बाद तालमेल पर आधारित। उन सभी को राज्यसभा में विपरीत स्थिति से निपटना पड़ा है। ऐसा इसलिए, क्योंकि उच्च सदन में अधिकतर सीटें उन चुनावों के जरिये भरी जाती हैं जिसमें विधायक मतदाता होते हैं और संघीय स्तर पर शासन करने के लिए चुनी गई पार्टी का इस सदन में बहुमत हासिल करने के लिए राज्य विधानसभाओं में पर्याप्त समर्थन नहीं होता। दोनों सदनों के रंग-ढंग के बीच यह अंतर पिछले पच्चीस साल की एक राजनीतिक सच्चाई है, लेकिन इसने पहले कभी जनादेश को पटरी से नहीं उतारा। ऐसे में अब हमें अल्पमत की ओर से किए जा रहे उत्पीड़न को लेकर जरूर चिंता करनी चाहिए।

(लेखक प्रसार भारती के प्रमुख हैं)

response@jagran.com

प्रणाली पर प्रश्नचिन्ह

◆ अगर एक निर्वाचित सरकार को अपने वादों को पूरा करने के लिए विधायी कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तो पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया व्यर्थ हो जाएगी

ऊर्जा

परोपकार

जिंदगी की सार्थकता दूसरों की भलाई करने में है। संसार में उसी परिश्रम को सार्थक कहा गया है जो दूसरों के लिए किया जाता है। वही मेहनत सफल कहलाती है, जिससे दूसरों का भला होता है। जीवन की किसी भी अवस्था में और किसी भी स्थिति में परोपकार किया जा सकता है। बस इसके लिए संवेदनशील और उदार भावनाएं चाहिए। प्राचीन समय में एक वृद्ध और बेसहारा आदमी भिक्षा मांगकर अपना जीवन-निर्वाह करता था। उसका नित्य का नियम था कि वह अधिक से अधिक भिक्षा प्राप्त करने का प्रयास करता था। इसी प्रयास में उसे सवेरे से लेकर रात हो जाती थी। वह भटकता रहता और हाथ पसारे भीख मांगता रहता। वृद्ध की दिनचर्या का एक हिस्सा यह भी था कि जैसे ही वह सबेरे सोकर उठता, सबसे पहले शुद्ध होकर मंदिर में जाता, वहां की पूजा में भाग लेता, भगवान को प्रणाम करता, फिर लौटकर आता और भीख मांगने निकल जाता। अपनी कुटिया से मुख्य मार्ग की ओर जाते समय वह अनाज के दानों से मुट्ठियां भर लेता और जहां पक्षियों को देखता, वहां दाने बिखेर देता। दोपहर को जब खाना खाने बैठता तो आधे से अधिक खाना लोगों में बांट देता। उसे अपना पेट भरने की अधिक चिंता नहीं होती थी जितनी दूसरे भूखे लोगों को होती थी। जिस दिन वह अधिक परमार्थ करता, उस रात उसे बड़ी गहरी नींद आती और वह निश्चिंततापूर्वक सो जाता।

सामान्यतः मनुष्य स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है और ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो केवल अपने लिए परिश्रम करते हैं। जो मनुष्य दूसरों के लिए नहीं सोचते, उनका जीवन व्यर्थ है। जीवन में सार्थकता तभी आती है, जब दूसरों के लिए कुछ किया जाता है। दूसरों की सहायता करने की प्रेरणा तो प्रकृति हर पल देती है, लेकिन मनुष्य फिर भी इनके शिक्षण से अनजान रहकर इनकी सेवा को ग्रहण करता रहता है। व्यक्ति के अंदर ऐसा जज्बा होना चाहिए कि जो उसकी राह में कांटे उत्पन्न करे उसके लिए भी वह फूल उत्पन्न कर सके। अंत में वह व्यक्ति स्वयं देखेगा कि उसके द्वारा उत्पन्न किए गए फूल तो फूल ही हैं, जबकि दूसरों द्वारा पैदा किए गए कांटे उनके लिए त्रिशूल बन गए हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति दूसरों का भला करते हैं, जिनके मन में परोपकार की भावना बलवती होती है, वे जिंदगी भर हंसते-मुस्कराते हैं।

◆ **डॉ. सुरचना त्रिवेदी**

जागरण Junction — AAPKI AWAAZ, AAPKA BLOG — www.jagranjunction.com

भारतीय सुरक्षा परिदृश्य

देश में आए-दिन पाक समर्थित आतंकियों द्वारा मनमाने तरीके से कहीं भी और कभी भी हमला बोल दिया जाता है, लेकिन इनसे निपटने के लिए भारत की जो तैयारियां होनी चाहिए वे अभी भी बहुत कमजोर हैं। 26/11 के मुंबई हमले के बाद निश्चित तौर पर भारतीय नेताओं की सोच में बदलाव आया है तथा सुरक्षा इंतजाम को और पुख्ता किया गया है। जम्मू-कश्मीर में पूरी सीमा की नाकेबंदी और चौकसी का स्तर बहुत ऊंचा कर दिए जाने के कारण आतंकी संगठनों के लिए वहां से घुसपैठ करना और हमला करना आसान नहीं रह गया है। इसलिए वे अब पंजाब और राजस्थान की सीमाओं पर नजरें गड़ाने लगे हैं। सवाल यह भी है कि किसी भी आतंकी हमले की स्थिति में क्या विभिन्न राज्यों की पुलिस के पास उतना प्रशिक्षण है जिसकी आवश्यकता होती है। जब भी कोई आतंकी हमला होता है तो असैन्य क्षेत्र में होने के कारण लगभग हर राज्य को सेना की कुशल टीमों की मदद की जरूरत तो होती है पर वे अपने राज्य के बलों की पीठ थपथपाने के लिए उन्हें ही आगे रखने का काम करते हैं। **– डॉ आशुतोष शुक्ल**

पूरा ब्लॉग पढ़ने के लिए यथावत टाइप करें : http://bit.ly/1TGP0Sr

महत्वपूर्ण है मिड-डे मील योजना

देश में नौनिहालों के पोषण, स्वास्थ्य व साक्षरता के स्तर को उन्नत करने के उद्देश्य से करीब दो दशक पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड-डे मील की शुरुआत की गई थी। यह योजना बहुत हद तक सफल साबित हुई। सामाजिक-आर्थिक समानता को समाज में पुनः स्थापित करने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस योजना के प्राथमिक विद्यालयों में लागू होने से एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। अब थाली लेकर ही सही, बच्चे विद्यालय तो पहुंच रहे हैं। विद्यालयों में उपस्थित रहने से कुछ शब्द तो उनके कान में पड़ ही जाते हैं। नियमित विद्यालय जाने से वह न सिर्फ पोषक भोजन ग्रहण कर रहे हैं, अपितु अनुशासन, खेल, सहयोग व सम्मान की भावना तथा नेतृत्व के गुण भी सीख रहे हैं। **– सुधीर कुमार**

पूरा ब्लॉग पढ़ने के लिए यथावत टाइप करें : http://bit.ly/1ZbCT6y

व्यर्थ का विचार

घरेलू शिक्षा पर खतरा शीर्षक से लिखे लेख में केसी त्यागी ने वर्तमान समय में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी निवेश के द्वार को खोलने को दीर्घकालिक दृष्टि से नुकसानदायक बताया है। इस समय जबकि देश के आइआइटी व अन्य नामचीन संस्थान नियुक्ति के लिए विदेशी अनुभव को न्यूनतम अर्हता मानते हैं तब देशी-विदेशी की वकालत करना औचित्यहीन है। सरकारी अनुदान के सवाल पर हमें यह भी सोचना होगा कि आजादी के बाद से कितना धन सरकार ने शिक्षा पर खर्च किया है। योग्यतम की उत्तरजीविता के कारण शिक्षा को खद्दर और लालफीताशाही से मुक्त करने से ही देश का भला होगा। सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में नियुक्ति, शिक्षकों की उपस्थिति, छात्रों का रुझान व अभिभावकों द्वारा किए जाने वाले खर्च और समाज में नैतिकता का ध्यान रखने पर ही स्थिति में सुधार संभव है। शिक्षा का क्षेत्र कृषि से अलग है और बेहतर तो तब होता जब विदेशी निवेश को प्राथमिक शिक्षा में आमंत्रित किया जाता।

रचना मिश्रा, सूखाताल, नैनीताल

नहीं मिला विश्वास

डेढ़ साल से अधिक हो गए मोदी जी को सरकार चलाते हुए, इतने कम समय में वे बतौर प्रधानमंत्री विश्व के कई देशों में भ्रमण किए जिनमें से कुछ जगह वे अपने प्रयास से गए व कुछ जगह औरों के प्रयास से गए। कहीं बुलाने पर गए तो कहीं अचानक ही पहुंच गए। इस दौरान वे खूब ख्याति अर्जित किए, लेकिन बात यह है कि इतने प्रचंड बहुमत वाली सरकार लोगों का विश्वास नहीं हासिल कर पाई। नतीजतन इसे लगातार हार का ही सामना करना पड़ रहा है, जिसका नमूना बिहार चुनाव के अलावा उत्तरप्रदेश का जिला पंचायत चुनाव रहा है, जिसमें भाजपा सात तो वहीं सपा 60 पर पहुंची है। इससे पहले उत्तरप्रदेश में ही लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव में पार्टी बुरी तरह हारी थी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश तथा बिहार वही राज्य हैं जहां से भाजपा सभी रिजनल पार्टियों को पटखनी देते हुए अच्छी खासी जीत दर्ज की थी, भाजपा के लिए समस्या की बात यह है कि वह अपनी तस्वीर विकास की बनाना चाहती है लेकिन जब चुनाव नजदीक आता है तो पार्टी के ही नेता बयान दे-दे कर यह जताने का प्रयास करने लगते हैं कि पार्टी का एजेंडा विकास के पहले मंदिर निर्माण का है, यही बात लोगों को समझ में नहीं आती।

सूरज तिवारी, नोएडा

पाठकनामा

pathaknama@nda.jagran.com

बदलने में भलाई

दिल्ली सरकार द्वारा प्रदूषण को कम करने के लिए चलायी गई सम-विषम योजना सफल होती दिख रही है। यह उन तमाम बौद्धिक तत्वों, तथाकथित चिंतकों एवम् विशेषज्ञों की सोच पर करारा तमाचा है जिन्होंने इस योजना के नुक्स निकालने शुरू कर दिए थे। आखिर क्या जरूरत पड़ जाती है कि ये लोग जन-हित की किसी शुरुआत को राजनीतिक रंग देने के साथ ही अपनी दुश्मनी निकालने का तरीका समझ लेते हैं। दिल्ली ने जब इस योजना का स्वागत बाहें फैलाकर किया है तो हमें इस पर आगे भी चलना चाहिए। महिला वर्ग को छूट मिलने पर भी उन्होंने कार पूलिंग और मेट्रो के विकल्प अपनाये। कितनी अच्छी बात है कि लोग फिक्रमंद हैं, शायद वे समझ चुके हैं कि भलाई हमें बदलने में ही है। जज, दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि और सबसे बड़ा आम जनता इसमें सहयोग कर रही है। अब इस से आगे बढ़कर बाइक पर भी यही नियम लागू करना चाहिए। हमें ही दिल्ली को विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी होने के चोगे से बाहर निकालना होगा। बदलाव हुआ है, अभी और बदलना है, हमें खुद को बदलना है।

जतिन कुमार, दिल्ली

विरोध क्यों?

आखिर कोई अयोध्या में राम-मंदिर का विरोध कैसे कर सकता है ? भगवान राम करीब 100 करोड़ हिंदुओं के आराध्य हैं और उनकी तुलना बाबर से नहीं की जा सकती। नदियां अनेक रास्ते से बहती हैं, लेकिन लक्ष्य तो समुद्र ही है। इसी तरह उपासना-पद्धति अलग हो सकती हैं, लेकिन लक्ष्य तो वही परमधाम है। फिर नफरत की जगह कहां है? राम मंदिर का विरोध क्यों?

जय प्रकाश झा, नई दिल्ली

जनपथ

साड़ी, कुर्ता, बूट पर संसद में हो बात,
सच बोली हैं सुप्रिया देनी चहिए दाद।
देनी चहिए दाद उन्हें दीजै शाबाशी,
बेबाकी हित बंधु चाहिए हिम्मत खासी।
दोषी हैं हम-आप चुनें हम निपट अनाड़ी,
वो संसद में जाय देखते कुर्ता-साड़ी।

-ओमप्रकाश तिवारी

ट्वीट ट्वीट

समझ नहीं आता कि एक देश जहां गाय की पूजा की जाती है वहां जल्लीकट्टू जैसी परंपरा कैसे कायम रह सकती है। वर्तमान में इक्वाडोर समेत तमाम देशों में इसे प्रतिबंधित किया जा चुका है।

- लिज मैथ्यू
@MathewLiz

आमिर खान अतुल्य भारत के लिए अब इसलिए अतुल्य नहीं रह गए हैं, क्योंकि वह अतुल्य वर्तमान सरकार की अपेक्षा के अनुरूप अतुल्य भाषा नहीं बोलते।

- अभिषेक सिंघवी
@DrAMSinghvi

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या सोनिया गांधी और वेंकैया नायडू की मुलाकात के बाद बजट सत्र में जीएसटी पारित होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं?

आज का सवाल

क्या आप ऑस्ट्रेलिया में होने जा रही वन-डे सीरीज में भारतीय टीम की जीत की उम्मीद कर रहे हैं?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y-हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम एसएमएस से प्राप्त नतीजों के साथ जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।